दैनिक भास्कर
गुड़गांव, सोमवार 21 जुलाई, 2008

ग्रामीण स्कूलों में शुद्ध पेयजल देने की तैयारी

गुड़गांव. ग्रामीण स्कूलों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सिस्टम की प्रदर्शनी का उद्घाटन करते और जानकारी देते डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हेड वाईपी कुमार। -भास्कर

इसी मद्देनजर रविवार को गुड़गांव में वाटर प्यूरीफायर सिस्टम की प्रदर्शनी आयोजित की गई।

भास्कर न्यूज. गुड़गांव

देश के तीस हजार ग्रामीण स्कूलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए वाटर प्यूरीफायर बनाने वाली कंपनियों की तलाश की जा रही है। इसी मद्देनजर रविवार को गुड़गांव में वाटर प्यूरीफायर सिस्टम की प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में उत्तर भारत की 26 कंपनियों ने देशी और विदेशी टेक्नोलॉजी से बने वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम का प्रदर्शन किया।

डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (डीएसटी) और कॉनफेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री (सीआईआई) द्वारा सामूहिक रूप से अयोजित इस सेमिनार में कंपनियों ने आधुनिकतम तकनीकी का प्रदर्शन करते हुए स्कूल में शुद्ध जल आपूर्ति करने का टिकाऊ और किफायती सिस्टम उपलब्ध करवाने दावा किया। इस दौरान कंपनियों ने पानी शुद्धिकरण की विदेशी तकनीक का भी प्रदर्शन किया।

मुकाबला काफी कठिन था। प्रत्येक कंपनी की तकनीक एक दूसरे से भिन्न थी। इस दौरा आईटीआरसी (लखनऊ) के वैज्ञानिक डा. केए दूबे, डीएसटी के डा. लक्ष्मण प्रसाद, वैकल्पिक विकास की डा. के विजयालक्ष्मी, टेहरी के अश्वनी और केके मारवाह की पांच सदस्यीय (ज्यूरी) टीम ने प्रत्येक कंपनी द्वारा प्रदर्शित की गई तकनीक का निरीक्षण किया। सिस्टम निर्माता व सप्लायर का अंतिम चयन पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा गठित कमेटी करंगी।

सेमिनार का उद्घाटन भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड वाईपी कुमार ने किया। इस अवसर पर कुमार ने ग्रामीण स्कूलों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने की सरकार की योजना की तकनीकी जानकारी दी। उन्होंने जानकारी दी कि इस योजना के तहत चार बड़े शहरों में सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। इन सेमिनारों के माध्यम से सरकार ग्रामीण स्कूलों के अनुकूल सिस्टम का चयन करने का प्रयास कर रही है।

तीस हजार स्कूलों में खर्च होंगे 200 करोड़ रुपए

उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी पेयजल योजना (आरजीएनडीडब्ल्यूएम) के तहत भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना के तहत देश के तीस हजार स्कूलों में वाटर प्यूरीफिकेशन सिस्टम लगाने के लिए वर्ष 2008-09 के दौरान 200 करोड़ रुपए बजट रखा गया है। इसके लिए भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति विभाग द्वारा एक हाई लेवल टेक्निकल कमेटी गठित की गई है। कमेटी का अध्यक्ष भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नॉलोजी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को बनाया गया है। कमेटी एक ऐसे सिस्टम की तलाश कर रही है, जो ग्रामीण वातावरण के अनुकूल हो और इसकी क्षमता एक हजार से 1500 लीटर पानी की सफाई करने की हो।